भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 477

जिसका उत्तर दिनांक 06.12.2023 को दिया जाना है

इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और निगरानी परियोजनाएं

477. श्री जी. एम. सिद्देश्वर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विभिन्न परमाणु और नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में राज्य-वार उन्नत और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और निगरानी परियोजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान निष्पादित परियोजनाएं और उनका मूल्य क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी निधियां आंवटित और उपयोग की गईं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) जी, हां। एनपीसीआईएल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसका अनुरक्षण अत्याधुनिक तरीके से सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। अन्य प्रावधानों के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक संरक्षा और निगरानी प्रणाली जैसे परिधि घुसपैठ संसूचक प्रणाली, अभिगम नियंत्रण प्रणाली, एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली, सीसीटीवी मॉनीटरन प्रणाली आदि सभी प्रचालित नाभिकीय बिजलीघर में सक्रिय रूप से मौजूद हैं। इन प्रणालियों को नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के अभिन्न अंग के रूप में कार्यान्वित किया गया है और आवधिक जांच, समीक्षा और आवश्यक उन्नयन के अधीन है।

(ख) व (ग) इन प्रणालियों के अनुरक्षण और उन्नयन के लिए पर्याप्त निधि आबंटित की जाती है। पिछले पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान इन प्रावधानों के अनुरक्षण और उन्नयन के लिए किया गया व्यय लगभग रुपए 118.79 करोड़ था।

* * * * *